फ़ैक्स संदेश संख्या 1302 /भा.कृ.अ.प. मुख्या.
दिनाँक 28/2/2014
पृष्ठों की संख्या 10

1/10

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN: NEW DELHI

F. No. FIN/22/06/2010-CDN (A&A) Dated the 27th Feb, 2014

SUB: Uploading Gazette Notification issued by the Govt. of India Resolution No.2-34/65-Reorgn (CC) dated the 30th March, 1966: Reg.

The Gazette Notification issued by the Govt. of India in reference to the "Resolution" No.2-34/65-Reorgn (CC) dated the 30th March, 1966 has been obtained from National Archives of India, Janpath, New Delhi. A copy of the same has been uploaded on ICAR Web-Site www.icar.org.in for information and further reference/guidance.

27/02/2014
(Rajesh Sahay)
Sr. Finance & Accts. Officer

Copy to:

1. Director (P)
2. DS (A)
3. DS (TS & WS)
4. US (TS & WS)
5. SO, Gov. Cell
6. SO, Per. IV
7. SO, Estt. I
8. SO, Work Study
9. SO, IF
10. SO, PIM
11. Incharge Library
12. PA to Director (Fin.)
13. Guard file-5
14. Shri Hans Raj, Information System officer, DKMA, FAB-I for posting the above mentioned letter with enclosure in the ICAR Web-site please.

28/02 2014 17:14 01123387293 ICAR HQ NEW DELHI #1140 P.002/010

रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16 1966 (चैत्र 26 1888)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16, 1966 (CHAITRA 26, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 30-मार्च 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 30th March 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
55	No. 159(1)/66-PY-I, dated 28th March 1966	Ministry of Food & Agriculture, Community Development & Co-operation.	Appointment of a Committee to examine the quantitative qualitative morphological and other characteristics of the different varieties of paddy grown in the country.
56	No. PN (U. K. Licensing) 2 of 1966, dated 30th March 1966.	Ministry of Commerce.	Regarding extending the free licensing of Export of Cotton yarn to U. K. upto 31st May 1966.
57	No. 41-ITC(PN)/66, dated 30th March 1966	Do.	Conversation of actual user licences for raw materials, components, spares and non-ferrous metal for April, 1965—March 1966 and April 1966—March 1967 period for importing steel and vice versa.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

(CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	325
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	333
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं ..	327
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—

28/02 2014 17:15 01123387293 ICAR HQ NEW DELHI #1140 P.003/010

3|10

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	617
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	1077
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश ..	107
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	249
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	141
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	43
भाग III—खंड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	251
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	91
पूरक सं० 16—	
9 अप्रैल 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	541
19 मार्च 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	553

	(Pages)
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	325
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	333
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	...
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	221
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations ..	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills ..	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	617
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1077
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	107
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	249
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	141
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	43
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	251
PART IV.—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	91
SUPPLEMENT No. 16—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 9th April 1966 ..	541
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 19th March 1966 ..	553

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1966

सं० आर० एस० 38/1/66-टी—श्रीमती वायलेट अल्वा 7 अप्रैल, 1966 को राज्य सभा की उपसभापति चुनी गई हैं।

वी० एन० बनर्जी, सचिव

वित्त मंत्रालय
(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1966

सं० एफ० 8(19)-एन० एस०/65—संसद सदस्य श्री रामेश्वर साहु को तत्काल भारत सरकार के 27 सितम्बर, 1965 के संकल्प संख्या एफ० 8(19)-एन० एस०/65 के अनुसार गठित राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।

परिणामतः, बचत संग्रह बोर्ड के सचिव, श्री के० वी० मडलेकर, राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सचिव के रूप में काम करना बन्द कर देंगे।

वी० एस० राजगोपालन, अनु सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1966

संकल्प

सं० 28-9/66-एफ० डी०—भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) और संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत के वन-साधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने के लिए 1-2-1965 को एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार और पूर्व दायित्व को निभाने के लिए, भारत सरकार ने एक केन्द्रीय समन्वय मण्डल की स्थापना की है।

2. केन्द्रीय समन्वय मण्डल, जिसे भविष्य में 'मण्डल' के नाम से पुकारा जाएगा, का संविधान और उसके कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे :—

संविधान

सभापति सचिव (कृषि विभाग) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार

सदस्य

भारत सरकार के वन महानिरीक्षक;

वित्तीय सलाहकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय;

अध्यक्ष, वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून;

भारत के सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि;

उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

सामुदायिक विकास विभाग का एक प्रतिनिधि;

योजना आयोग का एक प्रतिनिधि;

वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) का एक प्रतिनिधि;

परियोजना से सम्बन्धित सभी राज्यों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर और केरल) के मुख्य वन संरक्षक;

खाद्य एवं कृषि संगठन के उप-क्षेत्रीय प्रतिनिधि;

खाद्य एवं कृषि संगठन में योजना के सह निदेशक;

खाद्य एवं कृषि के वन तालिका के प्रवर विशेषज्ञ;

निर्जी वन आश्रित उद्योगों का एक प्रतिनिधि।

सदस्य-सचिव

उपवन महा निरीक्षक

मण्डल के सभापति को अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर, वह ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो कि मण्डल की बैठकों में उठाए गए प्रश्नों पर अपनी राय दे सकें, सहयोजित कर सकें। भारत में संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के कार्यक्रमों के निदेशक या उनके प्रतिनिधि, मण्डल की बैठकों में, स्थायी रूप से आमन्त्रित होंगे।

2. कार्यकलाप

परियोजना के कार्यक्रम के व्यापक आयोजन, निदेशन और समन्वय का दायित्व मण्डल पर होगा।

3. बैठकें

साधारणतः मण्डल की बैठकें वर्ष में दो बार होंगी। कोरम के लिए कम से कम पांच सदस्य होने चाहिए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि जन-साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र माथुर, संयुक्त सचिव

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1966

सं० 2-34/65- सीआर्ग० (सी० सी०)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जिम्मेदारियों और कार्यकलाप का निरीक्षण करने के उपरान्त, प्रथम भारत-अमरीकी दल (1955) इस निर्णय पर पहुंचा कि कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों में समन्वय लाने में परिषद् का नेतृत्व अप्रभावी रहा है अतः दल ने सिफारिश की है कि "परिषद् को विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञों के एक सुगठित कर्मचारी वर्ग के रूप में विकसित किया जाए जिससे कि परिषद् अपने उप-प्रधान के अधीन विशेष परामर्शदाताओं अथवा सलाहकारों की एक प्रवर परिषद् के रूप में कार्य कर सके।" दल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों के बीच अधिक ताल-मेल स्थापित करने की भी सिफारिश की जिसमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, परिषद् के परिचालन पक्ष (ओपरेटिंग विंग)

के रूप में कार्य करेंगे। द्वितीय भारत-अमरीकी दल (1959) ने अनुसंधान उत्तरदायित्वों की वर्तमान विषमताओं का अनुभव करके, पहले दल की सिफारिशों को अधिक जोरदार शब्दों में दोहराया। उन्होंने सिफारिश की है कि केन्द्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को समेकित करने तथा उसमें पर्याप्त समन्वय लाने के लिए, समस्त केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों और पण्य समितियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पूर्ण तकनीकी नियंत्रण में लाना चाहिए। 1963 में नियुक्त किये गये कृषि अनुसंधान पर्यवेक्षक दल ने उक्त सिफारिशों का जोरदार समर्थन किया है।

2. उक्त विशेषज्ञों के दल द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की सावधानी से जांच करने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को पूर्ण स्वायत्तशासी संगठन के रूप में पुनर्गठित करने और समस्त अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं जो कि अब खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, को पुनर्गठित परिषद् के पूर्ण प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण में लाने का निश्चय किया है। पुनर्गठित परिषद् के पहले ही अस्तित्व में आ जाने पर, भारत सरकार ने निम्नलिखित अनुसंधान संस्थानों, जिनमें उनके प्रादेशिक तथा उप-केन्द्र आदि भी सम्मिलित हैं, का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण, संस्थानों के सामने लिखी तारीख से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसायटी को स्थानांतर करने का निश्चय किया है :—

(i)	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1 अप्रैल, 1966
(ii)	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	
(iii)	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान	
(iv)	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	
(v)	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	
(vi)	केन्द्रीय मरुभूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	
(vii)	भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान	
(viii)	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	
(ix)	केन्द्रीय कन्द फसल अनुसंधान संस्थान	
(x)	गन्ना प्रजनन संस्थान	तारीख बाद में निश्चित की जायेगी।
(xi)	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	
(xii)	केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान	
(xiii)	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान	
(xiv)	केन्द्रीय मात्स्यकी टैक्नोलॉजी संस्थान	

3. सरकार ने ऊपर पैरा 2 में वर्णित संस्थानों की समस्त स्थावर तथा अस्थावर सम्पत्ति, परिसम्पत्ति (असेट) जिसमें दावे और अनुयोज्य (आक्शनेबल) दावे तथा ऋण और दायित्व भी सम्मिलित हैं, एक औपचारिक विलेख (डीड) अथवा विलेखों द्वारा, जो कि बाद में निष्पादित किये जायेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को स्थानांतर करने का निश्चय किया है।

4. भारत सरकार ऊपर लिखित पैराग्राफ 2 में वर्णित विभिन्न संस्थानों के क्रियाकलापों का खर्च चलाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को आवश्यक वार्षिक सहायता-अनुदान देगी।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासकों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रीमंडल के सचिवालय, प्रधानमंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये।

यह भी आदेश है कि यह संस्ताव जनसाधारण की सूचना के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० पी० नाग, अवर सचिव

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1966

सं० 2-7/66-रिआर्ग (सी०सी०)—डा० एस० हुसैन जहीर, महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् एवम् पदेन सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की प्रशासन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसका गठन खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, कृषि विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) के संस्ताव संख्या 2-7/66-रिआर्ग० (सी०सी०), दिनांक 17 फरवरी 1966 द्वारा किया गया है।

आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासकों और भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्री मण्डल के सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जायें।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारतीय राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

पी० एस० हरिहरन, अवर सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1966

सं० एफ० 16-6/65-पी० ई० 4—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 16-6/65-पी० ई० 4, दिनांक 1 मार्च, 1966 के क्रम में

एयर कमोडोर पी० एस० मेहता,
अध्यक्ष, सर्विसिस स्पोर्ट्स
कंट्रोल बोर्ड,

को मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोरा के स्थान पर "शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में केन्द्रीय संस्थानों के प्रशासनार्थ सोसायटी" के गवर्नर्स बोर्ड के पदेन सदस्य के रूप में आज की तारीख से 16-8-1966 तक नामजद किया जाता है।

दिनांक 19 मार्च 1966

सं० एफ० 1-2/65-पी० ई० 2—शिक्षा मंत्रालय की समसंख्यक, अधिसूचना दिनांक 2 मार्च, 1966 के क्रम में

डा० अमरिक सिंह,
सचिव,
भारत तथा श्रीलंका अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड,
रायज एवेन्यू, नई दिल्ली-2

को डा० बी० डी० लरोइया के स्थान पर अखिल भारतीय खेल परिषद् के एक सदस्य के रूप में आज की तारीख से 15 जुलाई, 1967 तक नामजद किया जाता है।

रोशनलाल आनन्द, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1966

सं० एफ० 16-1/66-पी० ई० 4—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 16-1/66-पी० ई० 4, दिनांक 1 मार्च, 1966 के क्रम में

श्री रोशन लाल आनन्द,
अवर सचिव,
शिक्षा मंत्रालय

को श्री के० पी० एस० आचार्य के स्थान पर 'लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर' के गवर्नर्स बोर्ड के एक सदस्य के रूप में आज की तारीख से नामजद किया जाता है।

ए० एस० बी० रोहतगी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 1966

सं० एफ० 11-16/64 सी०-1—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 11-3/64 सी०-1, दिनांक 23 अक्तूबर, 1964 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री पी० एन० पुष्प, निदेशक, पुस्तकालय तथा अभिलेखागार, श्रीनगर को श्री महमूद अहमद के स्थान पर, बोर्ड की शेष अवधि के लिए अर्थात् 31 अप्रैल, 1967 तक, जम्मू तथा काश्मीर सरकार के नामित के रूप में केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

शारदा राव (श्रीमती), सहायक शिक्षा सलाहकार

परिवहन तथा विमानन मंत्रालय

परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन विभाग

(परिवहन पक्ष)

पत्तन

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1966

सं० 17 पी० जी० (7)/66—भारत सरकार को 1964-65 की विशाखापत्तनम पत्तन की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट की उल्लेख योग्य बातें ये हैं :—

1. वित्तीय परिणाम

(क) पत्तन फंड : 1964–65 में पत्तन की राजस्व प्राप्तियां (कनहारो लेखा और विशेष प्राप्तियां छोड़कर) 253.16 लाख रुपये हैं। 1963–64 में यह प्राप्ति 216.96 लाख रुपये थी। आमदनी में वृद्धि का कारण यह था कि कच्चे लोहे और मैंगनीज की जहाजी लदान में वृद्धि हुई और मशीनरी भागों इत्यादि के अधिक आयात हुआ।

विचाराधीन वर्ष में व्यय (आरक्षित निधि के अंशदान, कनहारो लेखा में किये व्यय को छोड़कर) 198.88 लाख रहा। 1963–64 में यह संख्या 155.08 लाख रुपये थी। अधिक व्यय का मुख्य कारण यातायात कर्मचारियों में वृद्धि और श्रम के विभागीकरण पर अधिक व्यय तथा यातायात में वृद्धि के कारण ठेकेदारों द्वारा कच्ची धातु का धरा उठाया जाना, अधिक महंगाई भत्ते की अदायगी, संभरण और निपटान के महानिदेशक और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन से प्राप्त स्टोर के लिये अग्रिम अदायगी, पहुंच मार्गों में निकर्षण और टगों तथा लांचों पर अधिक व्यय तथा ऋण प्रभार में वृद्धि होना है।

(ख) कनहारी लेखा : 1964-65 में कनहारी लेखा के अन्तर्गत कुल आमदनी और खर्च क्रमशः 3.34 लाख रुपया और 2.55 लाख रुपया रहा। 1963-64 में ये संख्यायें 3.09 लाख रुपये और 2.1 लाख रुपया थीं। 1964–65 में 0.79 लाख रुपयों का अधिशेष रहा। 1963–64 में यह संख्या 0.99 लाख रुपया थी।

(ग) आरक्षित निधि : वर्ष के अन्त में विभिन्न फंडों के बारे में स्थिति संतोषजनक थी।

2. यातायात

(क) व्यापार : 1964–65 में इस पत्तन में 19.10 लाख टन का आयात हुआ। पिछले वर्ष यह संख्या 18.49 लाख टन थी। इस प्रकार 0.61 लाख टन की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण दवाइयों के अलावा रसायन पदार्थों (अमोनियम सल्फेट, गन्धक इत्यादि), खाद्यान्न, धातुओं, कच्ची धातुओं और रेलवे सामग्री के आयात में वृद्धि का होना है।

1964-65 में पत्तन से 19.63 लाख टन का निर्यात हुआ। पिछले वर्ष यह संख्या 16.72 लाख टन थी। इस प्रकार 2.91 लाख टन की वृद्धि हुई। वर्ष में जिन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई उन में से मैंगनीज, लोहा और क्रोम की कच्ची धातुयें भाइराबोलम और कच्ची धातुओं के अलावा अन्य धातु इत्यादि हैं।

(ख) नौवहन : 1964-65 में विदेशों को जाने वाले जहाज जो पत्तन में दाखिल हुए वे 23,31,909 कुल टन भार के 470 जहाज थे। पिछले वर्ष की ये संख्यायें 22,59,052 टन तथा 472 जहाज थीं। विचाराधीन वर्ष में 8,60,575 कुल टन भार के 233 तटीय जहाज पत्तन में आये। 1963-64 में यह संख्या 7,93,839 कुल टन भार तथा 206 जहाज थी।

1964-65 में पत्तन में आने वाला सबसे लंबा जहाज, 21,000 कुल टन भार का तथा 633 फीट (ओ० ए०) की लंबाई का एम० वी० "देश बन्धु" था। विचाराधीन वर्ष में पत्तन में आने वाला यही सब से अधिक गहरे डुबाव का जहाज था; इसका डुबाव आगे का 33 फीट और पीछे का 33 फीट लंबाई 633 फीट (ओ० ए०) और कुल टन भार 21,000 था।

3. श्रम : 1964-65 में श्रमिकों से संतोषजनक संबंध रहे।

4. पूंजीगत निर्माण कार्य : इस वर्ष कुल मिला कर 87.84 लाख रुपये के मूल्य के निर्माण कार्य किये गये। इस से युद्धोत्तर वर्षों में सम्पूर्ण पूंजी उद्व्यय लगभग 943 लाख रुपया का हो गया। 1964–65 में पत्तन के पूंजी-गत कार्यक्रम द्वारा सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो प्रगति पर थे ये हैं :—

1. अतिरिक्त चार यानों की स्कीम,
2. धातुक लादने का संयन्त्र,
3. दो पुल,
4. पनकट की विशेष मरम्मत, और
5. सूखी गोदी को लंबा और गहरा करना।

5. कर्मचारियों को सुविधायें

पोर्ट ट्रस्ट मंडल के कल्याणकारी उपायों में ये कार्य थे— खेलकूद, सांस्कृतिक-कार्यक्रम, कान्टीन और विश्राम कक्ष, क्लब, सहकारिता भंडार, निवासस्थान, बालकों के पार्क, सामान्य डाक्टरी देखभाल इत्यादि। सामान्यतया कर्मचारी कल्याणकारी निधि से जरूरतमंद कर्मचारियों, क्लबों इत्यादि को सहायता दी गई।

6. पोर्ट ट्रस्ट ने उपयोगी कार्य किया और 1964-65 में पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किये गये कार्य की सरकार सराहना करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संस्ताव की एक प्रतिलिपि समस्त संबद्ध को भेज दी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

के० सी० मादप्पा, संयुक्त सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1966

संकल्प

सं० ई० एल० 2–12(21)/61–जिल्द 2—दिल्ली में 50/62.5—50/62.5 मेगावाट के तीन सेटों के प्रतिष्ठापन के लिये दिल्ली ताप बिजली परियोजना नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना के बारे में इस मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या ई० एल० 2–12(21)/61 दिनांक 26 सितम्बर, 1962 में पैरा 2 की निम्नलिखित पद संख्या (3) को मिटा दिया जाए :—

(3) सिंचाई व बिजली उप-मंत्री—सदस्य।

710

2. पैरा 2 में वर्तमान मदों "(4) से (11)" को पुनः संख्यांकित कर "(3) से (10)" कर दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की पंजाब सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० पी० मथरानी, सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 7th April 1966

No. RS.38/1/66-T.—Shrimati Violet Alva has been chosen as the Deputy Chairman of the Council of States on the 7th April, 1966.

B. N. BANERJEE, Secy.

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 6th April 1966

SUBJECT :—*Long Vacation, 1966*

No. F.44/66-SCA-G.—In pursuance of Rule 4, of Order II, of the Supreme Court Rules, 1966, the Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, the 9th May, 1966, to Sunday, the 17th July, 1966 (both days inclusive) and will re-open on Monday, the 18th July, 1966.

The Hon'ble the Chief Justice of India has also been pleased under Rule 6, Order II of the aforesaid Rules, to appoint the Hon'ble Mr. Justice V. Ramaswamy and the Hon'ble Mr. Justice J. M. Shelat to be Vacation Judges to hear matters of an urgent nature, which under these Rules may be heard by a Judge sitting singly, for the respective period shown against their names below :—

The Hon'ble Mr. Justice V. Ramaswamy from the 9th may to the 12th June, 1966 (both days inclusive).

The Hon'ble Mr. Justice J. M. Shelat, from the 13th June to the 17th July, 1966 (both days inclusive).

The Hon'ble Mr. Justice V. Ramaswamy will sit on Tuesdays the 24th May and 7th June, 1966. The Hon'ble Mr. Justice J. M. Shelat will sit on Tuesdays, the 21st June and 5th July, 1966. Sittings will, however, continue on the next succeeding days if matters fixed for any day, are not finished on that day.

Except on Saturdays and holidays, the offices of the Court shall be open during vacation between 8 a.m. to 12.30 p.m. daily; but on the days notified for the vacation sittings the hours shall be 10 a.m. to 4.30 p.m.

No plaints, appeals, petitions or other documents, except those which require to be immediately or promptly dealt with will be filed or received in the Registry of the Court during the period the Court is in Vacation.

The Registry will open for filing purposes from Monday, the 18th July, 1966, but as from the 11th July, 1966, for the convenience of parties, the office of the Court will receive during the working hours all plaints, appeals, petitions, or other documents which may be ready for filing with the parties.

Y. D. DESAI, Registrar.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 6th April 1966

No. F. 8(19)-NS/65.—Shri Rameshwar Sahu, M.P. is appointed as Member-Secretary of the National Savings Central Advisory Board as constituted in the Government of India Resolution No. F. 8(19)-NS/65 dated the 27th September 1965, with immediate effect.

Shri K. A. Mandlekar, Secretary, Savings Mobilisation Board will consequently cease to function as Secretary, National Savings Central Advisory Board.

V. S. RAJAGOPALAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay-1, the 1st April 1966

No. 6/65-ER.—On the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet, the Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) set up under this Department's Notifications No. 10/2/61-ER dated February 16, 1962 and August 27, 1962 is reconstituted as follows :—

Chairman

(1) Dr. Vikram A. Sarabhai,
Director, Physical Research Laboratory,
Ahmedabad.

Members

(2) Dr. Vainu Bappu,
Director, Astrophysical Observatory,
Kodaikanal.

(3) Professor S. Dhawan,
Director, Indian Institute of Science
Bangalore.

(4) Shri S. N. Kalra,
Director General, Overseas Communication Service,
Bombay-1.

(5) Professor M. G. K. Menon,
Director, Tata Institute of Fundamental Research,
Bombay.

(6) Shri A. P. Mitra,
Assistant Director,
National Physical Laboratory,
New Delhi.

(7) Dr. P. R. Pisharoty,
Director, Institute of Tropical Meteorology,
Poona.

(8) Professor K. R. Ramanathan,
Physical Research Laboratory,
Ahmedabad & Chairman, Indian National Committee for IGY.

(9) Shri C. Ramaswamy,
Director General of Observatories,
India Meteorological Department,
New Delhi.

(10) Shri A. S. Rao, Director,
Electronics Group, Atomic Energy Establishment
Trombay, Bombay.

(11) Shri P. J. Rodgers, Director,
Experimental Satellite Communication Earth Station,
Ahmedabad.

(12) Shri H. N. Sethna, Director,
Atomic Energy Establishment Trombay,
Bombay.

(13) Dr. S. R. Valluri, Director,
National Aeronautical Laboratory,
Bangalore.

Member-Secretary

(14) Shri E. V. Chitnis,
Physical Research Laboratory,
Ahmedabad.

The terms of reference of the Committee remain unchanged.

R. SHROFF, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 30th March 1966

No. 1(1)/(Plant.A)/66.—With a view to ensuring that the Rajbari Tea Estate, which has recently been purchased by the Government of India and which is being managed on their behalf by M/s. Octavius Steel & Co. Ltd., Calcutta, is run on proper lines, the Government of India have decided to set up an Advisory Board to advise Government on all matters relating to the management and operation of the Tea Estate.

2. The Board shall consist of the following members :

Chairman

(1) Shri Bhagwan Singh,
Chairman, Tea Board,
14, Brabourne Road, Calcutta.

28/02 2014 17:23 01123387293 ICAR HQ NEW DELHI #1140 P.008/010

8/10

Members

(ii) Shri V. V. Parekh,
Managing Director,
M/s. J. Thomas & Co., Calcutta.

(iii) Shri R. Mahadevan,
Deputy Financial Adviser,
Commerce,
Ministry of Finance, New Delhi.

(iv) Shri S. Banerjee,
Deputy Secretary to the Government of India,
Ministry of Commerce, New Delhi.

Member-Convenor

(v) Shri W. H. G. Baird,
Managing Director,
M/s. Octavius Steel & Co. Ltd.,
14, Old Court House Street,
Calcutta.

3. The Managing Agents, M/s. Octavius Steel & Co. Ltd., Calcutta, will place all policy matters relating to the management of the Estate before the Board who will consider such matters and advise Government thereon.

4. The Board shall be constituted for a period up to the 31st January, 1967 and will normally meet at Calcutta.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. K. J. MENON, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

RESOLUTION

New Delhi, the 30th March 1966

No. 2-34/65-Reorgn.(CC).—The First Joint Indo-American Team (1955), after examining the activities and responsibilities of the Indian Council of Agricultural Research came to the conclusion that its leadership in coordinating agricultural research was ineffective, and accordingly recommended that "the development of the Council into a well rounded staff of specialists in the major problem fields to serve as a Senior Council of Special consultants or advisers under the Vice-President of the Council". The Team also recommended a closer working relationship between the Indian Council of Agricultural Research and the Central Research Institutes, in which the latter would function as an operating wing of the Council. The Second Joint Indo-American Team (1959), realising the prevalent diversity of research responsibilities, reiterated the recommendations of the First Team in even stronger terms. They recommended that in the interest of consolidating the Central Agricultural Research Programme and assuring adequate coordination, all the Research Institutes and Commodity Committees should be brought under the full technical and administrative control of the Indian Council of Agricultural Research. The Agricultural Research Review Team, appointed in 1963, has strongly supported the above recommendations.

2. After a very careful examination of the various recommendations made by the above Expert Team, the Government of India decided to reorganise the Indian Council of Agricultural Research as a fully autonomous organisation and bring under the full administrative and technical control of the reorganised Council, all the Research Institutions and Laboratories now under the administrative control of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation. The reorganised Council having already come into *existence*, the Government of India have now decided to transfer the full administrative control of the following Research Institutes, including their Regional and Sub-stations etc. to the Indian Council of Agricultural Research Society, with effect from the dates indicated there-against :—

(i) Indian Agricultural Research Institute;	1st April 1966
(ii) Indian Veterinary Research Institute;	
(iii) Central Rice Research Institute;	
(iv) Central Potato Research Institute;	
(v) National Dairy Research Institute;	
(vi) Central Arid Zone Research Institute;	
(vii) Indian Grassland and Fodder Research Institute;	
(viii) Central Sheep and Wool Research Institute;	
(ix) Central Tuber Crops Research Institute;	
(x) Sugarcane Breeding Institute;	to be Specified later
(xi) Indian Institute of Sugarcane Research;	
(xii) Central Inland Fisheries Research Institute;	
(xiii) Central Marine Fisheries Research Institute;	
(xiv) Central Institute of Fisheries Technology.	

3. Government have decided to transfer all movable and immoveable property, assets including claims and actionable claims and debts and liabilities of the Institutes mentioned in para 2 above to the Indian Council of Agricultural Research by a formal deed or deeds of transfer to be executed later. The nature and the form of the deeds would be determined later.

4. The Government of India will give requisite annual grants in aid to the Indian Council of Agricultural Research for financing the activities of the various Institutes mentioned in paragraph 2 above.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. P. PAL, Additional Secy.

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th April 1966

No. 28-9/66-FD.—Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation, (Department of Agriculture) and the Food & Agriculture Organisation of the United Nations Special Fund, have entered into an agreement on 1-2-1965 for undertaking a Pre-investment Survey of Forest Resources in India. In pursuance of the agreement and in fulfilment of its prior obligations, the Government of India have appointed a Central Coordination Board.

2. The constitution and functions of the Central Coordination Board hereafter called the Board will be as follows :

Constitution

Chairman

Secretary (Department of Agriculture) Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.

Members

Inspector General of Forests, Government of India.

Financial Adviser, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.

President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.

A representative of the Survey of India.

A representative of the Ministry of Industry.

A representative of the Ministry of Education.

A representative of the Department of Technical Development.

A representative of the Planning Commission.

A representative of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).

Chief Conservators of Forests of all States concerned with the Project (*viz.* Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Mysore and Kerala).

Food & Agriculture Organisation—Deputy Regional Representative.

Food & Agriculture Organisation—Project Co-Director.

Food & Agriculture Organisation—Senior Forest Inventory Specialist.

A representative of the private forest based industries.

Member-Secretary

Deputy Inspector General of Forests.

The Chairman of the Board will have the powers to co-opt, as and when required, such other persons as may be required to contribute to specific proposals for matters arising out of Board meetings. The Director of United Nations Special Fund activities in India, or his representative, will be a permanent invitee to Board's meetings.

3. *Functions* : The Board will be responsible for overall planning, direction and coordination of the project work.

4. *Meetings* The Board will meet ordinarily twice a year. Five members will constitute the quorum for a meeting.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

I. C. MATHUR, Jt. Secy.

(I.C.A.R.)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th April 1966

No. F.2(7)/66-Reorgn.(CC).—Dr. S. Hussain Zaheer, Director General, Council of Scientific & Industrial Research and *ex-officio* Secretary to the Government of India in the Ministry of Education is appointed as a member of the Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research, as constituted *vide* Resolution No. F.2-7/66-Reorgn.(CC), dated the 17th February, 1966 of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, Department of Agriculture (ICAR).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of the Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 29th March 1966

No. F.11-16/64.C1.—In partial modification of this Ministry's Notification No. F.11-3/64.C1, dated the 23rd October, 1964, Shri P. N. Pushp, Director, Libraries and Archives, Srinagar is appointed member of the Central Advisory Board of Archaeology as a nominee of the Government of Jammu and Kashmir *vice* Shri Mohumood Ahmed, for the remainder of the term of the Board *i.e.* up to 31st April 1967.

SHARDA RAO (MRS.), Asstt. Educational Adviser

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 4th April 1966

No. 14/2/66-SCT.II.—The Government of India have decided to extend the term of the Committee on Untouchability, Economic uplift and Educational Development of Scheduled Castes appointed under the Department of Social Security Resolution No. 14/5/64-SCT II, dated 27th April, 1965 for a further up to 30th June, 1966.

ORDER

ORDERED that the above be published in the Gazette of India.

S. C. SEN GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport, Shipping and Tourism)

(Transport Wing)

PORTS

RESOLUTION

New Delhi, the 1st April 1966

No. 17-PG(7)/66.—The Government of India have received the Administration Report of the Vishakhapatnam Port for the year 1964-65. The following are the noteworthy features in the Report :—

1. FINANCIAL RESULTS

(a) *Port Fund* : The revenue receipts of the port (excluding the Pilotage Account and Special receipts) during the year 1964-65, were Rs. 253.16 lakhs as compared with Rs. 216.96 lakhs during the year 1963-64. The increase in income was mainly due to the increase in shipments of iron ore, manganese ore, and also more imports of machinery parts, etc.

The expenditure (excluding contributions to Reserve Funds and expenditure charged to the Pilotage Account) during the year under review was Rs. 198.88 lakhs as against Rs. 155.06 lakhs in 1963-64. The larger expenditure was mainly due to increase in traffic staff and more expenditure on departmentalisation of labour and ore handling by contract due to increase in traffic, payment of increased dearness allowance, advance payments for stores obtained from the Director General of Supplies and Disposals and the India Supply Mission, Washington, more expenditure on dredging in approaches and on tugs and launches and increase in debt charges.

(b) *Pilotage Account* : The gross income and expenditure under the Pilotage Account during 1964-65 was Rs. 3.34 lakhs and Rs. 2.55 lakhs, respectively, as compared with Rs. 3.09 lakhs and Rs. 2.1 lakh, respectively, in 1963-64 with a surplus of Rs. 0.79 lakhs during the year 1964-65 as against a surplus of Rs. 0.99 lakhs in 1963-64.

(c) *Reserve Funds* : The position with regard to the balances in the various funds at the end of the year was satisfactory.

2. TRAFFIC

(a) *Trade* : The imports, which passed through the Port during the year 1964-65, was 19.10 lakh tonnes as against 18.49 lakhs tonnes in the previous year, registering an increase of 0.61 lakh tonnes. The increase was mainly due to increase in the import of chemicals other than medicines (Ammonium Sulphate, Sulphur, etc.), foodgrains, metals and ores, and Railway materials.

The exports during the year 1964-65, was 19.63 lakhs tonnes as against 16.72 lakhs tonnes in the previous year, registering an increase of 2.91 lakhs tonnes. Manganese, Iron and Chrome Ores, Myrabolams, and Metals other than ores etc. were the chief commodities the export of which increased during the year.

(b) *Shipping* : The number of foreign-going vessels, which entered the port during 1964-65, was 470 with a total tonnage of 23,31,909. The corresponding figures for the previous year were 472 and 22,59,052. 233 coastal vessels with a total tonnage of 8,60,575 visited the port during the year under review as against 206 with a total tonnage of 7,93,839 during 1963-64.

The M.V. "DESH BANDHU" of length 633' 0" (O.A.) with a gross registered tonnage of 21,000, was the longest vessel that entered the port during the year 1964-65. It was also the vessel with the deepest draft to enter the port during the year under review with draft forward 33' and Aft. 33' length 633' (O.A.) and G.R.T., 21,000.

3. LABOUR

Relations with labour continued to be satisfactory during the year 1964-65.

4. CAPITAL WORKS

Capital Works of an aggregate value of Rs. 87.84 lakhs were carried-out during the year, bringing the total capital outlay during the post-war years to about Rs. 943 lakhs. The most important items covered by the Capital programme of the port in progress during 1964-65 were :—

(i) Additional Four Berths Scheme;
(ii) Ore loading Plant;
(iii) Two Bridges;
(iv) Special repairs to breakwater; and
(v) Lengthening and deepening of Dry Dock.

5. AMENITIES TO STAFF

The Port Trust Board's welfare measures covered activities such as Sports, Cultural Programmes, Canteens and Rest Rooms, Clubs, Cooperative Stores, Housing, Children Parks, General medical attention, etc. As usual grants from the staff welfare Fund were given to needy employees, clubs etc.

6. ACKNOWLEDGEMENT

The Port Trust performed useful work and Government view with appreciation the work done by the Port Trust during the year 1964-65.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. MADAPPA, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 4th April 1966

No. EL.II-12(21)/61-Vol.II.—In this Ministry's Resolution No. EL-II-12(21)/61 dated the 26th September, 1962, relating to the constitution of the Delhi Thermal Project Control Board for the installation of 3 sets of 50/62.5 MW each, at Delhi, as amended from time to time, the following entry against serial number (3) in paragraph 2 may be deleted :—

(3) Deputy Minister for Irrigation & Power—*Member*.

2. In paragraph 2, the existing entries "(4) to (11)" may be renumbered as "(3) to (10)".

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to the Government of Punjab, the Delhi Administration, the Delhi Municipal Corporation, the Punjab State Electricity Board, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. P. MATHRANI, Secy.

28/02 2014 17:27 01123387293 ICAR HQ NEW DELHI #1140 P.010/010

RESOLUTION

New Delhi, the 5th April 1966

No. DW.V.502(10)/65.—In continuation of the Ministry's Resolution of even number dated the 10th February, 1966, the time for submission of the report by the Technical Committee constituted to review the present position of investigations on the Barak Dam Project and also to consider whether a dam should be constructed or alternative proposals have to be considered, is further extended up to the 30th June 1966.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to the State Government of Assam, the Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Comptroller and Auditor General of India and the Planning Commission for information.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Government of Assam be requested to publish it in the State Gazette for general information.

P. R. AHUJA, *Jt. Secy.*

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 1st April 1966

No. 24/5/66-HI.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Wadhawan, a permanent Officer of the Employees' State Insurance Corporation and former Member-Secretary, Employees' State Insurance Scheme Review Committee, as Officer on Special Duty in this Department to examine and process the recommendations of the aforesaid Committee with effect from the forenoon of the 1st April, 1966.

DALJIT SINGH, *Under Secy.*

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966